

प्रेषक,

डी0एस0 गर्ब्याल,

सचिव,

उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,

उत्तराखण्ड।

राजस्व अनुभाग-2

देहरादून: दिनांक: 18 जुलाई, 2016

विषय- प्रदेश में वर्ग-4 की भूमि के अवैध कब्जों एवं पट्टेदारों को भूमिधरी अधिकार प्रदान करते हुए विनियमितीकरण किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया, उपरोक्त विषयक शासकीय अधिसूचना संख्या-36/XXVI(III)/2014/11(1)/2014 दिनांक-27.01.2014 के द्वारा प्रदेश की सीमा के अन्तर्गत वर्ग-4 की ऐसी भूमि जिस पर व्यक्ति दिनांक-30.06.1983 अथवा उससे पूर्व अनाधिकृत रूप से काबिज थे तथा सम्प्रति इस भूमि पर काबिज हैं, पर जमींदारी विनाश एवं भूमि सुधार अधिनियम, 1950 की धारा-2 के अन्तर्गत प्रसार किया गया है, साथ ही ऐसे व्यक्तियों को सरकार द्वारा विहित प्रक्रिया के अनुरूप संक्रमणीय भूमिधर के अधिकार दिये गये हैं।

2- प्रदेश के जिला नैनीताल के तराई भावर क्षेत्र में राजकीय आस्थान एवं उपनिवेशन क्षेत्र की भूमि पर हुए प्राधिकृत कब्जों के विनियमन हेतु पूर्ववर्ती राज्य उत्तर प्रदेश द्वारा शासनादेश सं0-143/11/74(216) राजस्व-6 दि0-12.09.1975, शासनादेश सं0-143/11/74(216) राजस्व-6 दि0-28.06.1977, शासनादेश सं0-141/7/81(147)-रा0-6 दि0-05.10.1983 एवं शासनादेश सं0-150/3/84(204)-रा0-6 दि0-19.07.1989 निर्गत किये गये थे। उपरोक्त सन्दर्भित शासनादेशों में नैनीताल जनपद के तराई एवं भावर क्षेत्रों में सरकारी भूमि पर हुए 1381 फसली (30 जून, 1974) से पूर्व के अनाधिकृत कब्जों को विनियमित किये जाने की व्यवस्था सुनिश्चित की गयी थी। राज्य गठन के उपरान्त वर्ग-4 की भूमि के अवैध कब्जों को विनियमित किये जाने के सम्बन्ध में शासनादेश सं0-453/XVIII(II)/2014-07(46)/2008 दि0-11.03.2015 में निहित व्यवस्था के अनुसार दि0-30.06.1983 अथवा उससे पूर्व अनाधिकृत रूप से काबिज व्यक्तियों को राज्य सरकार द्वारा विहित प्रक्रिया के अनुसार संक्रमणीय भूमिधर के अधिकार दिये गये हैं। इसी प्रकार शासनादेश सं0-1846/XVIII(II)/2015-07(46)/2008 दि0-26.11.2015 के द्वारा विहित प्रक्रिया के अनुसार वर्ग-4 की भूमि के पट्टेदारों को भूमिधरी अधिकार प्रदान करते हुए विनियमित किया गया है।

3- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश में वर्ग-4 की भूमि के अवैध कब्जों को विनियमित किये जाने के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश सं0-453/XVIII(II)/2014-07(46)/2008 दि0-11.03.2015 एवं वर्ग-4 की भूमि के पट्टेदारों को भूमिधरी अधिकार प्रदान किये

44

जाने के सम्बन्ध में शासनादेश सं०-1846/XVIII(II)/2015-07(46)/2008 दि०-26.11.2015 को एतद्वारा अतिक्रमित करते हुए वर्ग-4 की भूमि के अवैध कब्जों एवं पट्टेदारों को भूमिधरी अधिकार प्रदान करते हुए विनियमितीकरण की समयावधि शासनादेश निर्गत होने की तिथि से 01 वर्ष किये जाने का निर्णय लिया गया है। उक्त दोनों वर्गों के भूमि के विनियमितीकरण के लिए निम्न सिद्धान्त एवं शर्तें होंगी :-

- (1) जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 (उत्तराखण्ड में यथाप्रवृत्त) की धारा-132 के अन्तर्गत आने वाली भूमि (सार्वजनिक उपयोग जैसे चकमार्ग, गूल, खलिहान, कब्रिस्तान, शमशानघाट, चारागाह आदि) का विनियमितीकरण नहीं किया जायेगा।
- (2) जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 (उत्तराखण्ड में यथाप्रवृत्त) की धारा-132 के अन्तर्गत आने वाली भूमि (सार्वजनिक उपयोग जैसे चकमार्ग, गूल, खलिहान, कब्रिस्तान, शमशानघाट, चारागाह आदि) पर यदि अवैध कब्जा पाया जाता है तो उसे पहले खाली कराया जायेगा और तब उस अध्यासी/पट्टेदार की अन्य वर्ग-4 की भूमि का विनियमितीकरण किया जायेगा।
- (3) अध्यासी/पट्टेदार की वर्ग-4 की भूमि का विनियमितीकरण करने से पूर्व तहसीलदार को यह प्रमाण पत्र देना होगा कि जिस अध्यासी/पट्टेदार की वर्ग-4 की भूमि विनियमित की जा रही है, उस अध्यासी/पट्टेदार के पास धारा-132 के अधीन आने वाली भूमि अवैध कब्जे में नहीं है।
- (4) वर्ग-4 की उस भूमि का विनियमितीकरण, जिसका वाद मा० न्यायालय में लम्बित है, इस शर्त के अधीन किया जायेगा कि विनियमितीकरण मा० न्यायालय द्वारा पारित अंतिम निर्णय के अधीन होगा।
- (5) वर्ग-4 की भूमि के विनियमितीकरण की इस नीति में शासनादेश संख्या-883/X-3-2011-8(21)/2010 दिनांक-04.10.2011 के निर्देशों का अनुपालन किया जायेगा।
- (6) वर्ग-4 की भूमि के सिंचित/असिंचित भूमि में श्रेणीबद्ध किया जायेगा तथा भूमि के सिंचित होने पर विनियमितीकरण हेतु निर्धारित सर्किल रेट के 1.5 गुने के आधार पर नजराना लेकर कार्यवाही की जाय। असिंचित भूमि की दर निर्धारित सर्किल रेट के अनुसार होगी। यह व्यवस्था अध्यासी/पट्टेदार पर समान रूप से लागू होगी।
- (7) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति, अन्त्योदय व बी०पी०एल० की अपनी भूमि को सम्मिलित करते हुए वर्ग-4 की उतनी ही भूमि का विनियमितीकरण निःशुल्क किया जाये, जिसको मिलाकर उनके पास कुल 3.125 एकड़ भूमि से अधिक भूमि न हों अर्थात् अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्त्योदय तथा बी०पी०एल० वर्ग के व्यक्ति की अपनी भूमि सहित 3.125 एकड़ तक भूमि का विनियमितीकरण निःशुल्क किया जायेगा।

- (8) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्त्योदय एवं बी०पी०एल० के कब्जेदारों के लिए उनकी अपनी एवं वर्ग-4 के कब्जे की भूमि को मिलाकर 3.125 एकड़ से अधिक, परन्तु 12.5 एकड़ से अनाधिक भूमि के विनियमितीकरण कब्जे की अवधि का भू-राजस्व का बीस गुना तथा जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित सर्किल रेट का 12 प्रतिशत नजराना लेकर किया जाए, जो 04 समान किस्तों में 03-03 माह में एक वर्ष के भीतर जमा किया जायेगा।
- (9) अन्य सामान्य वर्ग के लिए अपनी भूमि को सम्मिलित करते हुए वर्ग-4 की उतनी ही भूमि का विनियमितीकरण, कब्जे की अवधि का भू-राजस्व का बीस गुना तथा जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित सर्किल रेट के 08 प्रतिशत नजराना लेकर किया जाय, जो 04 समान किस्तों में 03-03 माह में एक वर्ष के भीतर जमा किया जायेगा, जिसको मिलाकर उनकी कुल भूमि 3.125 एकड़ तक हो जायेगी।
- (10) अन्य सामान्य वर्ग के व्यक्ति के पास वर्ग-4 की भूमि को सम्मिलित करते हुए विनियमितीकरण के बाद 3.125 एकड़ से अधिक भूमि है, तो उसकी 6.25 एकड़ तक की भूमि का विनियमितीकरण कब्जे की अवधि का भू-राजस्व का बीस गुना तथा जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित सर्किल रेट का 20 प्रतिशत नजराना जमा करने पर किया जाए, जो 04 समान किस्तों में 03-03 माह में एक वर्ष के भीतर जमा किया जायेगा।
- (11) यदि किसी व्यक्ति के पास वर्ग-4 की भूमि को सम्मिलित करते हुए 6.25 एकड़ से अधिक भूमि है तो उसकी 12.5 एकड़ (अधिकतम सीलिंग सीमा) तक भूमि का विनियमितीकरण कब्जे की अवधि का भू-राजस्व का बीस गुना तथा जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित सर्किल रेट का 32 प्रतिशत नजराना जमा करने पर किया जाए, जो 04 समान किस्तों में 03-03 माह में एक वर्ष के भीतर जमा किया जायेगा।
- (12) वर्ग-4 की भूमि पट्टेदारों को संक्रमणीय अधिकार दिये जाने हेतु पट्टेदार द्वारा पूर्व में जमा की गयी धनराशि को वर्तमान में विनियमितीकरण हेतु निर्धारित धनराशि में समायोजित कर दिया जायेगा।
- (13) वर्ग-4 की भूमि के 3.125 एकड़ से अधिक के विनियमितीकरण के प्रस्ताव शासन को सन्दर्भित किये जाने के बजाय जिलाधिकारी अपने स्तर से ही निस्तारित करेंगे।
- (14) नगरीय क्षेत्र में सभी के लिए वर्ग-4 की 100 वर्ग मीटर तक की भूमि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/बी०पी०एल०/अन्त्योदय को निःशुल्क तथा शेष को भूमि का विनियमितीकरण कब्जे की अवधि का भू-राजस्व का दोगुना तथा जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित सर्किल रेट का 20 प्रतिशत नजराना लेकर किया जाए, जो 04 समान किस्तों में 03-03 माह में एक वर्ष के भीतर जमा किया जायेगा।
- (15) इस परिप्रेक्ष्य में शासनादेश संख्या- 150/3/89/(206)-राजस्व-06 दिनांक- 19.07.1989 में

दी गयी व्यवस्था के अनुसार जिन्होंने (30.06.1974 तक के अवैध कब्जे एवं पट्टेदारों) विनियमितीकरण हेतु सम्पूर्ण धनराशि दिनांक-31.12.1989 तक जमा कर दी है, उनका विनियमितीकरण बिना किसी अतिरिक्त नजराना लिये, किया जाय।

- (16) विनियमितीकरण हेतु पात्र अध्यासियों/पट्टेदारों की पहचान उनका नाम खतौनी के श्रेणी-4 में अंकित अभिलेख से ही किया जायेगा। खतौनी में अंकित व्यक्ति के ऐसे भूमि पर कब्जे का सत्यापन तहसील स्तर पर किया जायेगा तथा सत्यापनकर्ता अधिकारी द्वारा इस आशय का प्रमाण पत्र दिया जायेगा।
- (17) वर्ग-4 के ऐसे अध्यासी/पट्टेदार जिनकी मृत्यु वर्ष 1390 फसली के बाद हुई हो, उनके वारिसान के पक्ष में अभिलेखीय पुष्टि करने के पश्चात् विनियमितीकरण कर दिया जाये कि जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 में निहित प्राविधान के अनुसार मृतक अध्यासी/पट्टेदार के उत्तराधिकारी ही प्रश्नगत भूमि पर काबिज हैं।
- (18) खतौनी के वर्ग-4 के ऐसे खातों में जहां अनाधिकृत अध्यासियों/पट्टेदारों का नाम संयुक्त रूप से अंकित है और उनमें, भिन्न-भिन्न परिवारों के व्यक्ति भी शामिल हैं, ऐसे मामलों में यदि किसी डीड के आधार पर संयुक्त अध्यासियों/पट्टेदारों के हिस्से भिन्न-भिन्न हैं, तो उसी के अनुसार विनियमितीकरण किया जाय, अन्यथा उनके हिस्से बराबर मानकर कार्यवाही की जाय। इस बात का भी ध्यान रखा जाय कि संयुक्त कब्जे की भूमि उपरोक्तानुसार पट्टे पर दिये जाने से किसी व्यक्ति के परिवार के पास विनियमितीकरण के उपरान्त सीलिंग सीमा से अधिक भूमि न हो।
- (19) जिन मामलों में विधिक कठिनाईयां होंगी या अन्य दावेदारों द्वारा भी विनियमितीकरण का अनुरोध किया जायेगा तो ऐसे सभी मामलों को परीक्षणोपरान्त निर्णय हेतु संस्तुति सहित शासन को सन्दर्भित किया जायेगा।
- (20) प्रदेश में वर्ग-4 की भूमि पर अनाधिकृत काबिज जो अध्यासी उक्त योजना का लाभ प्राप्त कर विनियमितीकरण नहीं करायेंगे, उनके विरुद्ध नियमानुसार बेदखली की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।
- (21) उपरोक्त कार्यवाही के लिए जिले के जिलाधिकारी के द्वारा वर्ग-4 के अनाधिकृत कब्जों एवं पट्टेदारों को भूमिधरी अधिकार दिये जाने के सम्बन्ध में व्यापक प्रचार प्रसार किया जायेगा तथा भूमि के विनियमितीकरण हेतु जिलाधिकारी के द्वारा अभियान चलाकर स्वयं मासिक समीक्षा की जायेगी तथा विनियमितीकरण हेतु विशेष शिविर आयोजित किये जायेंगे।
- (22) उक्त सभी मामलों में विनियमितीकरण की प्रक्रिया समयबद्ध आधार पर पूर्ण करने तथा उपरोक्त पात्रता का अनुपालन करने हेतु सम्बन्धित जिलाधिकारी उत्तरदायी होंगे तथा उनके द्वारा मासिक आधार पर इस प्रक्रिया की समीक्षा एवं अनुश्रवण भी किया जायेगा।

14/

(23) उपरोक्त सीमा तक वर्ग-4 की भूमि के अवैध कब्जाधारकों एवं शासनादेश दि०-28.09.2006 के आधार पर विनियमित वर्ग-4 की भूमि के पट्टेदारों को संक्रमणीय भूमिधर के अधिकार दिये जाने की प्रक्रिया उपरोक्तानुसार निर्धारित की गयी है। उपरोक्त भूमि के विनियमितीकरण की अवधि शासनादेश निर्गत किये जाने की तिथि से एक वर्ष तक निर्धारित की गयी है, जिसे अभियान के रूप में पूर्ण कराने का दायित्व सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी का है।

4- प्रदेश में वर्ग-4 की भूमि के पट्टों के विनियमितीकरण एवं अवैध कब्जों को विनियमितीकरण हेतु प्राप्त भू-राजस्व शुल्क/नजराने की धनराशि को राजस्व प्राप्तियों के अन्तर्गत लेखा शीर्षक 0029-भू-राजस्व-00-101 भू-राजस्व/कर-02 सरकारी आस्थानों से उगाहियाँ-किसानों से लगान-09 प्रकीर्ण के अन्तर्गत राजकोष में जमा कराया जायेगा।

अतः अनुरोध है कि उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराते हुए नियमित रूप से विनियमितीकरण की प्रगति एवं कृत कार्यवाही से मासिक आधार पर राजस्व परिषद एवं शासन को निर्धारित प्रपत्र पर अपेक्षित सूचनायें उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(डी०एस० गब्याल)
सचिव।

संख्या-804 (1)/XVIII(II)/2016 एवं तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निजी सचिव, मा० मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
2. निजी सचिव, मा० राजस्व मंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
5. आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद उत्तराखण्ड, देहरादून।
6. आयुक्त, गढ़वाल/कुमाऊँ मण्डल, पौड़ी/नैनीताल।
7. महानिदेशक सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
8. निदेशक, एन०आई०सी० सचिवालय परिसर, उत्तराखण्ड।
9. विभागीय पुस्तिका।

आज्ञा से,

(जे०पी० जोशी)
अपर सचिव।